

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन

- 1 कोई भी भारत का नागरिक जन सूचना अधिकारी को आवेदन करके किसी भी लोक प्राधिकारी से संबंधित जानकारी दस्तावेज य अभिलेख प्राप्त कर सकता है।
 - 2 आवेदन करता को आवेदन के साथ 10/-रु० आवेदन शुल्क अदा करना होगा।
 - 3 सूचना निम्नलिखित फीस की दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी
- सूचना का विवरण**
- क) आवेदन सहित फीस
 - ख) जहां सूचना प्रकाशन मूल्य के रूप में उपलब्ध है
 - ग) प्रकाशित मूल्य से अन्यथा के लिए
 - घ) जहां सूचना एलेक्ट्रोनिक स्वरूप में उपलब्ध है और एलेक्ट्रोनिक स्वरूप में दी जानी है जैसे फॉलोपि व सीडी इत्यादि
 - ड) अभिलेख/दस्तावेज के निरिक्षण के लिए फीस
 - भुगतान कोष चालान मांगे ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से होगा।
 - 5 गरीबी रेखा में आने वाले व्यक्तियों को आवेदन शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है।
 - 6 सूचना अस्तीकार करने या आवेदक का संतोषजनक उत्तर न मिलने की रिथ्ति में आवेदन 30 दिनों के अंदर अपील प्राधिकारी को सूचित कर सकता है। दूसरी अपील 90 दिनों के भीतर राज्य सूचना आयोग में दायर की जा सकेगी अपील दायर करने के लिए सूचना अस्तीकार करने या आवेदक का संतोषजनक उत्तर न मिलने की रिथ्ति में आवेदन 30 दिनों के अंदर अपील प्राधिकारी को सूचित कर सकता है।
 - 7 सूचना निम्नलिखित आधार पर अस्तीकार की जा सकती है:-
- क) सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा रणनीति, वेजानिक या निदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या किसी अपराध को करने का उदीयपन होता है।
 - ख) सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद किया गया है या जिसके प्रकाशन से न्यायालय का अपमान होता है।
 - ग) सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान मंडल के विशेषाधिकार का भंग करीत होगा।
 - घ) सूचना जिसमें वाणिज्यक विश्वास व्यापार गोपनीयता या बोधविक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी रिथ्ति को नुकसान होता है।
 - ड) किसी व्यक्ति को उसकी वेशाधिकार नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक की सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना को प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है।
 - च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।
 - छ) सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के विश्वास में दी गयी किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा।
 - ज) सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण पकड़े जाने या अभियोजन की किया में अडचन पड़ेगी।
 - झ) मंत्रिमंडल से कागजपत्र जिसमें मंत्रिपरिषद सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है।

परंतु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या पश्चात जनता को उपलब्ध करवाए जाएंगे।

परंतु यह ओर कि वह विषय जो इस धारा में विनिदिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं प्रकट नहीं किए जाएंगे।

अपील प्राधिकारी

निदेशक

स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन
हिमाचल प्रदेश शिमला-2

जन सूचना अधिकारी एवं ए०डी०सी०

स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन
हिमाचल प्रदेश शिमला-2
(0177-2621383)